क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रेस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

पेजः 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्षः 1 अंकः 147, गुरुवार, 21 जून 2018, पेजः 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिसः- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

केजरीवाल का धरना नौटंकी : तिवारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के धरने को धरना नौटंकी की संज्ञा देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सवाल किया है कि केजरीवाल किस मांग को लेकर धरने पर बैठे थे और किसके आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया। दिल्ली सरकार की इस नौटंकी से दिल्लीवासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल के एक और ड्रामे का पटाक्षेप हो गया। केजरीवाल एक गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री के साथ ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। बिजली-पानी से जूझ रही दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने जो भद्दा मजाक किया है कि वह माफी के लायक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने सचिवालय में धरने पर बैठे नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता, सांसद प्रवेश वर्मा, मनजिन्दर सिंह सिरसा, जगदीश प्रधान एवं कपिल मिश्रा को भी धरना समाप्त करने को कहा।

उत्तराखंड के पूर्व सीएम की एस्कार्ट में लगी गाड़ी से महिला घायल

अमरोहा (एजेंसी)। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की एस्कार्ट ड्यटी में लगी पुलिस की गाड़ी ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि महिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खाता गांव में दवाई लेने जा रही थी। महिला संभल के दहपा की निवासी है। घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद महिला को मेरठ में भर्ती कराया गया है।

लेडी कांस्टेबल के साथ महिला की भिड़ंत का वीडियो वायरल, एक-दूसरे का बाल खींचती आईं नजर

देवरिया (एजेंसी)। जमीन को लेकर झगड़े की सूचना पर पहुंची डायल-100 की पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसकी सूचना पर खुखुन्दू पुलिस मौके पर पहुंची, तो हमलावर महिला ने लेडिज कांस्टेबल के बाल पकड़ कर पटक दिया। पुलिस महिला को गिरफ्तार कर थाने ले गई। इस घटना का वीडिया वायरल होने पर पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। इस मामले में सिपाही की तहरीर पर खुखुन्दू थाने में आठ के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।

जमीन के विवाद में हुई मारपीट

खुखुन्दू थाना क्षेत्र के टड़वा गांव की रहने वाली फूलमती पत्नी रामबेलास का गांव के ही रामाश्रय से भूमि का विवाद है। पिछले दिनों पुलिस की उपस्थिति में दोनों की भूमि का चिन्हाकंन कर दिया गया फूलमती बुधवार को अपनी भूमि पर दिवार का निर्माण कराने लगी। इसका विरोध करते हुए रामाश्रय और उसके परिजनों ने फूलमती को मारपीट कर घायल कर दिया। इसकी सूचना पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची, तो रामाश्रय के परिजनों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया।

पुलिस से भिड़ी महिला

डायल 100 पुलिस ने कंट्रोल से सुरक्षा की मांग की। इसकी जानकारी होने पर खुखुन्दू पुलिस महिला सिपाही के साथ गांव में पहुंची। जहां एक महिला लेडी कांस्टेबल से भिड़ गई। उसने महिला सिपाही के बाल पकड़ कर पटक दिया। महिला सिपाही उसे पकड़ कर थाने ले आई। महिला ने अपना नाम केवली देवी बताया। पुलिस ने महिला सिपाही का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। महिला सिपाही को बाल पकड़ कर खींचने का वीडियो वायरल हो गया है।

कई धाराओं में मुकदमा दर्ज

इस मामले में डायल 100 के सिपाही अशोक कुमार की तहरीर पर खुखुन्दू थाने में आठ लोगों के खिलाफ धारा 147, 323, 332, 336, 352, 353 और 504 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस महिला कांस्टेबल पर हमला करने वाली केवली देवी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। रामाश्रय और उसके परिजनों की तलाश में पुलिस ने टड़वा गांव में छापेमारी की।

»»» उपराज्यपाल से मिलने का मांग रहे थे समय

आप विधायकों को पुलिस ने निकाला

नई दिल्ली (एजेंसी)। आप विधायक सोमनाथ भारती और एसके बग्गा को मंगलवार को पुलिस ने उपराज्यपाल कार्यालय से कथित तौर पर निकाल दिया।

डीडीए की एक बैठक में शरीक होने के लिए वहां गए भारती और बग्गा उपराज्यपाल से मिलने के लिए समय मांग रहे थे।

वहीं , राजनिवास के एक बयान में दावा किया गया है कि बैठक समाप्त होने के बाद विधायक सोमनाथ भारती और एसके बग्गा ने मुख्यमंत्री के धरना में शामिल होने के बहाने उपराज्यपाल के आवासीय परिसर की ओर जाने की कोशिश की।

दोनों विधायकों को एलजी के आवासीय परिसर से चले जाने का बार-बार अनुरोध किया गया।

बयान के मुताबिक, भारती और बग्गा ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और वहां अवैध रूप से दो घंटे तक टिके रहे। समझाने बुझाने के बाद ही वे वहां से निकले। हालांकि एलजी कार्यालय में 11 जून से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर कहा कि यह एलजी का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करें। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि दो विधायकों को एलजी ने पुलिस के जरिए जबरन निकाला।

सिर्फ इसलिए कि वे उनसे मिलना चाहते थे।

क्या हो रहा है? एलजी विधायकों, सांसदों , मुख्यमंत्री से मिलने से क्यों इनकार कर रहे हैं ? क्या एलजी जानते हैं कि इन लोगों से मिलना उनका संवैधानिक कर्तव्य है।

यह आश्चर्यजनक है । हालांकि कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारती और बग्गा को एलजी ने मिलने का कोई वक्त नहीं दिया था और उनसे वहां से जाने को कहा गया।

घरेलू कलह से बढ़ा गुस्सा

गुस्से में पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास,फरार

नई दिल्ली (एजेंसी)। घरेलू कलह से गुस्साए एक जल्लाद शख्स ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। घटना बाहरी दिल्ली के निहाल विहार इलाके की है, जहां वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। बताया जाता है कि जलती हुई महिला जब घर में इधर से उधर दौड़ रही थी, तब उसके बच्चों ने पानी डालकर आग बुझाई और मामले की सूचना पुलिस को दी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया।

डॉक्टरों के मुताबिक महिला 90 प्रतिशत तक झुलस गई और फिलहाल स्थिति नाजुक है।

इसकी पुष्टि करते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की पहचान ममता (40) के रूप में की गई है।

पुलिस ने इस संदर्भ में आरोपी सुरेन्द्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है। जांच में पता चला कि आरोपी सुरेन्द्र एसी रिपेयरिंग का काम करता है और नशे का आदी है। बताया जाता है कि पीड़ित महिला की सुरेन्द्र के साथ दूसरी शादी है। महिला के दो बच्चे मेरठ में रहते हैं। जिन बच्चों ने आग बुझाई, वे कुछ दिन पहले ही मेरठ से अपनी मां से मिलने आए थे।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक देर रात खाना खाने के दौरान सुरेन्द्र ममता से अभद्र तरीके से बात कर रहा था, जिसका बच्चों ने जब विरोध किया तो सुरेन्द्र ममता से झगड़ा करने लगा। झगड़े के बीच ही सुरेन्द्र ने ज्वलनशील पदार्थ लाकर ममता के ऊपर उड़ेल दिया और आग लगाकर फरार हो गया।

गिर अभयारण्य में अब प्रशिक्षित कुत्ते करेंगे शेरों की सुरक्षा

अमरेली। गुजरात के गिर अभयारण्य में एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित कुत्तों के दस्ते तैनात होंगे। ये दस्ते शेरों के मूवमेंट पर नजर रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड्स की मदद करेंगे। दरअसल, राज्य सरकार सिंहों की हर मूवमेंट पर नजर रखना चाहती है। इसके लिए सिंह मित्र नाम से यूनिट बनाई गई है। इन्हीं सिंहमित्रों को प्रशिक्षित कुत्तों के दस्ते देने की योजना है।

»»» उपराज्यपाल से मिलने का मांग रहे थे समय

आप विधायकों को पुलिस ने निकाला

नई दिल्ली (एजेंसी)। आप विधायक सोमनाथ भारती और एसके बग्गा को मंगलवार को पुलिस ने उपराज्यपाल कार्यालय से कथित तौर पर निकाल दिया।

डीडीए की एक बैठक में शरीक होने के लिए वहां गए भारती और बग्गा उपराज्यपाल से मिलने के लिए समय मांग रहे थे।

राजनिवास के एक बयान में दावा किया गया है कि बैठक समाप्त होने के बाद विधायक सोमनाथ भारती और एसके बग्गा ने मुख्यमंत्री के धरना में शामिल होने के बहाने उपराज्यपाल के आवासीय परिसर की ओर जाने की कोशिश की। दोनों विधायकों को एलजी के आवासीय परिसर से चले जाने का बार-बार अनुरोध किया गया।

बयान के मुताबिक, भारती और बग्गा ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और वहां अवैध रूप से दो घंटे तक टिके रहे। समझाने बुझाने के बाद ही वे वहां से निकले। हालांकि एलजी कार्यालय में 11 जून से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर कहा कि यह एलजी का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करें। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि दो विधायकों को एलजी ने पुलिस के जरिए जबरन निकाला।

सिर्फ इसलिए कि वे उनसे मिलना चाहते थे। क्या हो रहा है? एलजी विधायकों, सांसदों, मुख्यमंत्री से मिलने से क्यों इनकार कर रहे हैं ? क्या एलजी जानते हैं कि इन लोगों से मिलना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। यह आश्चर्यजनक है। हालांकि कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारती और बग्गा को एलजी ने मिलने का कोई वक्त नहीं दिया था और उनसे वहां से जाने को कहा गया।

एलजी के अंदर वायसराय की आत्मा : संजय सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)। आप ने मंगलवार को फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एलजी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बैजल के अंदर वायसराय की आत्मा प्रवेश कर गई है।

संजय सिंह ने दावा किया कि आईएएस अधिकारी सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आास्त किया है कि वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सिंह ने कहा है कि आईएएस अधिकारी और सरकार दोनों गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उपराज्यपाल बैठक नहीं बुला रहे, जिससे हमारा आरोप साबित होता है कि वह नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह नवाज शरीफ (पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री) से मिल सकते हैं, लेकिन पिछले आठ दिनों से एलजी दफ्तर में धरना पर बैठे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा है कि (आजादी से पहले) वायसराय एलजी हाउस में रहते थे, जहां अब बैजल रहते हैं।

ऐसा लगता है कि वायसराय की आत्मा उनमें समा गई है। आप के प्रवक्ता दिलीप पांडेय ने दावा किया कि आईएएस अधिकारियों ने ''निजी बातचीत' में काम पर आने की अच्छा जाहिर की है, लेकिन वे एलजी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने तक आईएएस अधिकारी अपनी इच्छा के बावजूद काम पर नहीं लौट सकते।

»»» एक ही कुनबे के थे चारों

तालाब में नहाने गए चार बच्चों की डूबने से मौत

मोदीनगर (एजेंसी)। गाजियाबाद से सटे मोदीनगर में भोजपुर थाने के गांव त्यौड़ी सात बिस्वा में मंगलवार दोपहर गांव के बाहर तालाब में नहाते समय चार बच्चे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने तालाब से डूब रहे चारों बच्चों को निकालकर हापुड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीन को मृत घोषित कर दिया गया। चारों बच्चे गांव में एक ही कुनबे के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, असलम परिवार के साथ गांव के बाहरी तालाब के पास बने मकान में रहता है। मंगलवार दोपहर असलम का बेटा रेहान (13) उसका छोटा भाई दानिश (09), चचेरे भाई असद (08) पुत्र इकराम और गांव के ही मुजस्सिम (10) पुत्र सरफराज और मोहम्मद माज (09) पुत्र डॉ. शोएब के साथ तालाब के पास खेल रहे थे।

खेलते-खेलते पांचों बच्चे गर्मी के कारण तालाब में नहाने लगे। नहाते समय दानिश, मुजस्सिम, माज और असद तालाब के गहरे पानी में चले गए और पानी में डूबने लगे। चारों को डूबता देख किनारे पर नहा रहे रेहान ने शोर मचा दिया, जिससे शोर सुनकर तालाब पर पहुंचे ग्रामीणों ने चारों बच्चों को काफी मशक्कत के बाद तालाब से बाहर निकाला। बेसुध चारों बच्चों को आनन-फानन में हापुड़ के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दानिश, मुजस्सिम और मोहम्मद माज को मृत घोषित कर दिया, जबकि असद को गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया, जिसे मेरठ के जगदम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां देर रात असद की भी मौत हो गई।

> ग्रामीणों ने तालाब से डूब रहे चारों बच्चों को निकालकर हापुड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीन को मृत घोषित कर दिया गया। चारों बच्चे गांव में एक ही कुनबे के बताए जा रहे हैं।

मामले की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में नेता व अन्य लोग गांव में पहुंच रहे हैं। वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया है।

»»» गोगी गैंग का शॉर्पशूटर हेमचंद्र

गैंगवार में मारा गया दूसरा बदमाश

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोमवार को उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में टिल्लू व गोगी गैंग के बीच हुए गैंगवार के दौरान दो बदमाश व एक महिला समेत दो राहगीरों की मौत हो गई थी, वहीं तीन बदमाश समेत पांच लोग घायल भी हो गए थे।

मरने वाले दोनों बदमाशों में से एक का शव घटनास्थल पर ही मिल गया था, जबकि दूसरे का शव शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल के सामने से बदमाशों की फॉच्यरूनर कार में पड़ा मिला था। जिसे उसके साथी कार समेत अस्पताल के पास छोड़कर फरार हो गए थे। कार में मिले बदमाश के शव की पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हुआ।

शुरूआत में उसकी पहचान संजीत के रूप में हुई थी, लेकिन छानबीन में पता चला कि संजीत नामक बदमाश तो फिलहाल जेल में बंद है।

जिसके बाद पूछताछ व अन्य सूत्रों के माध्यम से पुलिस को पता चला कि मृत अपराधी की पहचान हरियाणा के झज्जर निवासी हेमचंद्र है, जो गोगी गैंग का शॉर्प शूटर था।

पुलिस को साथ ही पता चला कि बरामद फॉच्यरूनर कार बदमाशों ने गुरुग्राम इलाके से लूटी थी। गैंगवार की गंभीरता को देखते हुए 300 पुलिसकर्मियों की 15 टीमों ने अबतक 50 सेज्यादा जगहों पर छापेमारी करते हुए सौ से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। लेकिन फिलहाल हमले के आरोपियों तक पहुंचने में नाकाम रही है। जानकारी के अनुसार उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, बाहरी व रोहिणी जिले के अलावा क्राइम ब्रांच व स्पेशल सेल की कई टीमें सघन छापेमारी कर रही हैं।

शवों का किया गया पोस्टमार्टम : गैंगवार में मारे गए सभी लोगों का मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया। जहां मारे गए पहलवान 16 वर्षीय मुकुल को चार गोलियां लगने का पता चला, वहीं हेमचंद्र को पांच गोलियां लगी पाई गई। इसमें मारी गई राहगीर महिला को एक गोली लगी बताई जा रही है।

जांच में पता चला कि इस गैंगवार के दौरान 9 एमएम की पिस्टल का इस्तेमाल भी किया गया था।

भाई की हत्या का चश्मदीद गवाह है पवन, उसके पास था लाइसेंसी हथियार : पवन नामक युवक के पास लाइसेंसी हथियार मौजूद था, साथ ही उसे दिल्ली पुलिस से पीएसओ भी मिला हुआ है। बताया जाता है कि जनवरी 2015 में पवन के सगे भाई राजू की हत्या कर दी गई थी, जिसमें वह अहम गवाह है। इसलिए उसके जान पर खतरे को देखते हुए उसे पीएसओ मिला हुआ है। दरअसल पवन के भाई राजू की हत्या जितेंद्र उर्फ गोगी व उसके साथी कुलदीप, जरनैल सिंह जैली और योगेश ने किया था। इस अहम केस की पैरवी में पवन के साथ उसका भांजा मुकुल भी था। जिसकी गैंगवार में हत्या कर दी गई।

100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ 50 से ज्यादा जगहों पर की गई छापेमारी

संपादकीय

समर्थन वापसी

साढ़े तीन साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में राजनीति का जो एक अध्याय शुरू किया था, मंगलवार की दोपहर उसके समापन की घोषणा हो गई। तब सरकार चलाने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से गठजोड़ की जितनी तरह की राजनीतिक व्याख्याएं हुई थीं, उतनी ही तरह की व्याख्याएं शायद इस संबंध-विच्छेद की भी होंगी। बहुत से लोगों को अभी से इसमें उम्मीद नजर आनी शुरू हो गई है। यह मानने वालों की तादाद काफी बड़ी है कि अब ऑपरेशन ऑल आउट की सारी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। अब सुरक्षा बलों को अपना काम करने की खुली छूट दी जाएगी और वे आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में पूरी तरह जुट जाएंगे। इस सोच के पीछे कहीं न कहीं यह धारणा भी है कि भाजपा और पीडीपी का गठजोड़ आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में आड़े आ रहा है। लेकिन भाजपा के इस कदम की एक दूसरी व्याख्या भी है। यह भी कहा जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में सरकार से समर्थन वापस लेकर पार्टी ने अगले आम चुनाव की राजनीति शुरू कर दी है। इस व्याख्या में कुछ नया नहीं है। आम चुनाव जब पास आने लगता है, तो किसी भी पार्टी के हर कदम की सबसे सुगम व्याख्या यही हो सकती है। ऐसी व्याख्याएं अक्सर गलत भी नहीं होतीं।. यह भी सच है कि पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में जो हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार और भाजपा, दोनों के लिए ही कोई बड़ा कदम उठाना और साथ ही कुछ करते हुए दिखना जरूरी हो गया था। प्रदेश सरकार से समर्थन वापस लेकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। यह भी तय है कि अगला कदम राष्ट्रपति शासन होगा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा देकर इसका रास्ता भी साफ कर दिया है। यह उम्मीद कम ही है कि वहां वैकल्पिक सरकार बनाने का कोई दावा सामने आए। ऐसे में, इस बदलाव का अर्थ होगा राज्य की बागडोर का केंद्र के हाथ में आ जाना। केंद्र सरकार अब वहां अपने ढंग से आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने को स्वतंत्र होगी। वैसे अभी भी यह अभियान केंद्रीय सुरक्षा बलों और सेना के जरिये ही चलाया जा रहा था। लेकिन इसमें केंद्र सरकार को एक सुविधा मिली हुई थी। वह सफलताओं को अपने खाते में दर्ज करा सकती थी और नाकामियों के आरोप राज्य के मत्थे मढ़ सकती थी। यह सुविधा अब खत्म हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती के लिए भी अच्छा है कि वह केंद्र और भाजपा विरोध की राजनीति फिर जोर-शोर से शुरू कर सकेंगी। साझा सरकार का होना उन्हें अभी तक इससे रोक रहा था।. भाजपा ने जब पीडीपी को समर्थन दिया था, तब इसकी एक व्याख्या यह हुई थी कि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस जैसी पार्टियां जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक यथार्थ हैं और इस सच को स्वीकार करके ही वहां की राजनीति आगे बढ़ाई जा सकती है। भाजपा द्वारा पीडीपी को समर्थन देने को इस सच को स्वीकार करने के रूप में ही देखा गया था। जाहिर है, पिछले साढ़े तीन साल में भाजपा को इस सच की सीमाएं भी नजर आ ही गई होंगी। फिलहाल केंद्र सरकार को बिना ज्यादा राजनीतिक सोच-विचार के कश्मीर घाटी में खुलकर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का मौका मिल गया है। इससे काफी उम्मीदें भी हैं। लेकिन उसके आगे जब राज्य में फिर से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी, तो यह सच और इसकी सीमाएं फिर से सबके सामने खड़ी होंगी। .

राजस्व पर फोकस

केंद्रीय मंत्री अरु ण जेटली की इस अपील को खारिज करना संभव नहीं है लोग अपना कर ईमानदारी से अदा करें। देश को चलाने के लिए जो धन चाहिए उसका मुख्य स्रेत कर राजस्व ही है। यह भी सच है कि हमारा देश अभी तक कर अनुपालन वाला समाज नहीं बन पाया है। इस स्थिति को बदले की आवश्यकता है। वित्त मंत्री जबसे किडनी ट्रांसप्लांट कराके अस्पताल से बाहर आए हैं, अपनी बात वो फेसबुक के माध्यम से कह रहे हैं। इस बार उन्होंने राजकोष से लेकर अर्थव्यवस्था की स्थिति रोजगार सृजन आदि पर प्रकाश डाला है। किंतु उनका मुख्य फोकस कर राजस्व ही है। उनके पूरे पोस्ट का भाव यही है कि यदि देश को कर राजस्व के लिए पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करनी है तो फिर अन्य क्षेत्र में करों की वृद्धि करनी होगी। यहां तक तो बात समझ में आती है। किंतु कई बार बातें सच होते हुए भी राजनीति में उसके कहने का तरीका अलग होता है। आप ऐसी भाषा न बोलें, जिससे राजनीतिक नुकसान होने की संभावना बढ़ जाए। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने पेट्रोल, डीजल पर से 25 रु पया तक कर कम करने का जो वक्तव्य दिया वह एक राजनीतिक वक्तव्य था। देश के आम व्यक्ति को भी अंदाजा है कि यह संभव नहीं। जेटली का यह कहना भी सही है कि उनके पूर्ववर्ती ने स्वयं अपने शासनकाल में ऐसा नहीं किया। पर इसी के साथ सीधे रु खी भाषा में यह कह देना कि उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं की जाएगी, राजनीतिक रूप से जोखिम भरा है। हम यह भी मानते हैं कि देश जिस स्थिति में है यदि तेल पर से उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की जाएगी तो फिर सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा एवं धीरे-धीरे हम कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। तेल से करों में कटौती का असर उत्पादकता पर भी पड़ेगा। किंतु इस समय जब तेल के मूल्य कम करने की मांग हो रही है, सरकार की ओर से बयान आ रहे हैं कि वह ऐसे उपायों पर विचार कर रही है, जिससे इसका दीर्घकालीन समाधान निकले, वित्त मंत्री के सीधे कर कटौती से इनकार करने की जनता के बीच नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। बिना इसके भी अपनी बात कही जा सकती थी। जेटली भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें पता होगा कि इस वर्ष के विधानसभा चुनाव वाले तीन राज्यों में उनकी सरकार है और उसके बाद 2019 में आम चुनाव होना है। विपक्षी उनके इस पोस्ट को उद्धृत करके जनता को भाजपा के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे।

चौं रे चम्पू/अशोक चक्रधर

धरती किसी को नहीं गिराती

चौं रे चम्पू! हड़ताल और धरना एकई चीज ऐं का?-नहीं, दोनों भिन्न हैं, दोनों में द्वैत है। हड़ताल स्त्रीलिंग, धरना पुल्लिंग। हड़ताल करने वाला हड़ताली और धरना करने वाला धरनैत। अद्वैत नहीं है इनमें। हड़ताल, जीवन से जुड़ी मांगों के लिए कामबंदी, लामबंदी, चक्काजाम, मोर्चा, और बंद के रूप में व्यापक असहयोग से प्रकट होती है। धरना के प्रस्थानिबंदु हैं अनशन और सत्याग्रह। वैसे, धरना के अनेक अर्थ हैं। जैसे अपराधी को पकड़ो तो उसको धर दबोचना है, धरना। आप अपनी बगीची में कोई माली नियुक्त करो तो वह है, माली धरना। धरना को क्रिया मानें तो, संभल-संभल पग धरना। अब इस धरना के नये उच्चस्तरीय रूप देखने को मिल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने एलजी के यहां जो धरना दिया, वह धरना नहीं है, अनामंत्रित पधरना है, जिसके यहां धरना दिया जाए वह आपकी पद-गरिमा देखते हुए रोके-टोके नहीं, ये है ''पधरना'। एलजी किसी और घर में बैठे हुए ''एलजी' के टीवी पर अपने घर का ''पधरना' देख रहे हैं। मिलने की संवैधानिक बाध्यता संदिग्ध है। जिन कारणों से आदरणीय का पधरना हुआ उनसे तालमेल बैठे तो मिल भी बैठें। धरना पीएमओ तक चल पड़ा। धरनाधर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। यह कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में सदियां उफान पर रही हैं आजकल पूर्वोत्तर में नदियां उफान पर हैं, उसकी किसे फिकर?-तौ तू धरना-हड़ताल कूं बेकार मानैं? -बेकार क्यों मानूंगा चचा? लेकिन जरा सोचें, पूर्ण राज्य कैसे बन सकती है दिल्ली? क्या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार पर शासन कर सकती है? धरना के नये आयामों को देखें तो वह बखेड़ा, लफड़ा, टंटा, ऊधम, झंझावात, हुल्लड़, हलचल, हंगामा और हड़कंप बनने लगा है। हमारे कुछ मंच के कवियों ने तो ये सारे अपने उपनाम बना लिये। अपने नामों को उन्होंने कभी सार्थक नहीं किया लेकिन। हुल्लड़ जी नहीं रहे, वे काव्य-मर्मज्ञ थे। इन सारे कवियों ने ऐसे नाम इसलिए रखे क्योंकि धरना का सबसे अच्छा रूप मानते हैं, ''सुधरना'। धरती को कष्ट होता है इस प्रकार के धरनों से, पर बिठाती तो वही है। तुम अपने आप गिरो तो गिरो, धरती किसी को नहीं गिराती। यह उसका बड़प्पन है।

और उलझ गई कश्मीर की राजनीति

> भाजपा और पीडीपी गठबंधन में दरार तो काफी पहले आ गई थी। पर इसका तात्कालिन कारण बना रमजान के दौरान किया गया युद्ध-विराम।

आरती आर जेरथ

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी-भाजपा सरकार का गिरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निजी नुकसान की तरह है। उन्होंने अपनी पार्टी और संघ परिवार के आक्रामक हिंदुत्ववादियों के खिलाफ जाकर पीडीपी के साथ गठबंधन बनाने में रुचि दिखाई थी। गठबंधन सरकार बनने के एक वर्ष के भीतर निवर्तमान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद भी यह गठबंधन कायम था। मगर कार्यकाल पूरा करने से पहले ही करीब सवा दो वर्ष के भीतर महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। इससे केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर भी सवाल उठेंगे ही।

इस गठबंधन में दरार तो काफी पहले आ गई थी, पर तात्कालिक कारण साबित हुआ है रमजान के दौरान किया गया युद्ध-विराम। केंद्र द्वारा युद्ध-विराम को रद्द किए जाने और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन फिर से शुरू करने संबंधी फैसला लिए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती की हैसियत एक अधिकार-विहीन मुख्यमंत्री जैसी हो गई थी। श्रीनगर से ऐसे मजबूत संकेत आ रहे थे कि महबूबा गठबंधन से बाहर निकलने की योजना बना रही हैं। वह इस सप्ताह नई दिल्ली भी आने वाली थीं, ताकि सरकार बचाने की आखिरी कोशिश कर सकें। मगर भाजपा ने पहले ही गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। वैसे तो महबूबा मुफ्ती से एक कदम आगे निकलकर भाजपा ने खुद को तुष्ट करने की ही कोशिश की है, लेकिन इस पूरे मामले का स्याह पहलू यह है कि नई दिल्ली ने उस वक्त कश्मीर को अकेला छोड़ दिया है, जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान फिर से घाटी की बदहाल स्थिति की तरफ है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त जेद-अल राद हुसैन ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से यह अपील करेंगे कि वह 'कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की एक समग्र स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच' करे। उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन पर अपनी तरह की संयुक्त राष्ट्र की पहली रिपोर्ट भी जारी की है। भारत के लिए यह राहत की बात हो सकती है कि उन्होंने हमारे और पाक अधिकृत, दोनों कश्मीर की बात की। मगर सच यही है कि 1990 के दशक के दौरान, जब घाटी में आतंक चरम पर था और कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर हमारे ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहे थे, तब भी संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी ने कोई आधिकारिक जांच की बात नहीं की थी।

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले अमेरिकी प्रशासन की तुलना में कश्मीर में कम रुचि जरूर दिखाई है, पर चीन का गरम रुख अब भी कायम है। हमारे लिए चीन का दबाव अमेरिकी हस्तक्षेप से निपटने की तुलना में कहीं अधिक कठिन साबित हो सकता है। भारत में चीन के राजदूत ल्यू झाओहुई ने भी हाल ही में कश्मीर मसले पर एक त्रिपक्षीय वार्ता (भारत, पाकिस्तान और चीन) की वकालत की थी, जिसे बिना सोचे-समझे दिया गया कोई निजी बयान नहीं मानना चाहिए। चूंकि यह सुझाव शंघाई सहयोग संगठन के तहत तीनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के संदर्भ में दिया गया था, इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कश्मीर में शांति की दरकार हो सकती है। ऐसे में, तब राजदूत के बयान का निहितार्थ चीन के लिए है कि वह कश्मीर सहित तमाम मतभेदों को दूर करने के लिए भारत और पाकिस्तान को वार्ता की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत ने बेशक ऐसे सुझावों की कड़ी आलोचना की है और उसे तत्काल खारिज कर दिया है, लेकिन यह भी एक संकेत हो सकता है कि इस्लामाबाद ने अपने 'हरदम अजीज दोस्त' से भारत के साथ अपने विवादों के निपटारे के लिए मदद मांगी हो।

हाल के दिनों में ये कुछ ऐसी तस्वीरें थीं, जो कश्मीर के मुश्किल हालात में दुनिया भर से उठ रही थीं। ऐसे में, श्रीनगर में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार से समर्थन वापस लेकर मोदी सरकार ने खुद को अंतरराष्ट्रीय दबाव के निशाने पर ही ले लिया है।

सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? निश्चय ही आने वाले दिन केंद्र सरकार के लिए मुश्किलों भरे रहने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगते ही सेना और अन्य तमाम सुरक्षा बलों को घाटी से आतंकवादियों के सफाए के लिए खुली छूट मिल जाएगी। इसका किस हद तक और क्या लाभ मिलेगा, यह अभी बता पाना मुश्किल है। मगर मेरा मानना है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की सख्ती घाटी में दिखाई गई है, उसने कश्मीर को पहले की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर किया है। आज कश्मीर में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वह कोई धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक जंग है, जो भारत देश के खिलाफ लड़ी जा रही है, और इस समस्या में वहां हर कोई शामिल हो चुका है। यही वजह है कि वहां के कई माता-पिता अपने 'पत्थरबाज' बच्चों की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में, यदि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाएगा, तो इससे वहां भविष्य में शांति का लक्ष्य पाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है।

जम्मू-कश्मीर की राजनीति के मौजूदा दो बड़े चेहरे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की सियासत के लिए भी ताजा घटनाक्रम किसी झटके से कम नहीं है। एक साल के भीतर देश भर में आम चुनाव होने वाले हैं। अभी घाटी के जिस तरह के हालात हैं, उसमें कश्मीर की तीनों सीटों- बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग में शांतिपूर्ण चुनाव कराना काफी मुश्किल काम होगा। लगातार हिंसा की वजह से महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई अनंतनाग सीट पर उप-चुनाव भी नहीं करवाए जा सके। हालांकि श्रीनगर में उप-चुनाव हुए जरूर थे, लेकिन वहां भी वोट प्रतिशत घाटी में अब तक का सबसे कम महज सात रहा था। (ये लेखिका के अपने विचार हैं)

ग्राम न्यायालय योजना

ग्रीन कार्ड अभिलाषियों को लाल झंडी

अमेरिकियों को तरजीह

प्रमोद भार्गव

11906199ष्स्र द्दह्लह्नद्धश्चश्चअमेरिकी नागरिक बन जाने की प्रबल इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए बुरी खबर सामने आई है। यहां ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वालों की सूची इतनी लंबी हो गई है कि कई लोगों को 151 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिका के केटो इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन के बाद यह जानकारी दी है। यह जानकारी अमेरिका के नागरिकता व आव्रजन सेवा विभाग द्वारा हाल ही में जारी आवेदनों की संख्या पर आधारित है। इधर ब्रिटेन में भी उस सूची में भारतीय छात्रों को शामिल नहीं किया गया है जो ब्रिटेन आने वाले छात्रों को वीजा हासिल करने की सुविधा देती है। अमेरिका व चीन के बाद ब्रिटेन में सबसे ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ने जाते हैं। जबकि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने 25 देशों के छात्रों को वीजा देने वाली सुविधा सूची जारी की है।

अमेरिकी ग्रीन कार्ड पाने की लालसा में जिन भारतीयों ने अर्जियां लगाई हुई हैं, उनकी संख्या 6,32,219 है। जबकि अमेरिकी कानून के हिसाब से किसी एक देश को कुल जारी किए जाने वाले ग्रीन कार्ड का 7 प्रतिशत से ज्यादा देने का प्रावधान ही नहीं है। चुनांचे इस कोटे के चलते सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ रहा है क्योंकि सबसे लंबी सूची उन्हीं की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'अमेरिकी-प्रथम' की जो धारणा बनाई हुई है, उसके चलते यह गुंजाइश भी न्यूनतम है कि उनके चलते कोटे में कोई बढ़ोतरी की जाएगी। वर्ष 2017 में 22,602 भारतीयों को ग्रीन कार्ड जारी किए गए थे। अमेरिका में बसने की इच्छा रखने वालों में दूसरे पायदान पर चीनी नागरिक हैं। इनकी संख्या 67,031 है। इसके बाद अल-साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, फिलीपींस, मेक्सिको और वियतनाम के प्रवासी हैं। किंतु इनमें से किसी भी देश के आवेदकों की संख्या 10,000 से अधिक नहीं है।

यही नहीं, इसी जून माह में अमेरिका उन लाखों भारतीय महिलाओं को भी नमस्ते कर सकता है, जिनके जीवन साथी वहां पहले से ही नौकरियों में हैं। दरअसल ट्रंप-प्रशासन एच-1 बी वीजा के उस प्रावधान को रद्द कर सकता है, जिसके तहत पति व पत्नी दोनों अमेरिका में रहकर नौकरी कर सकते थे। अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देने के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है। ओबामा सरकार ने ऐसी प्रतिभावान पत्नियों को काम करने की अनुमति एच-1 बी वीजा के तहत दी हुई थी, जो कंपनियों की योजनाओं को अमल में लाने में सक्षम थीं। इस कारण वहां अनेक उच्च शिक्षित भारतीय गृहिणियों को नौकरियां मिली हुई हैं। उन्हें यह सुविधा 'स्पेशल वर्क परमिट' के जरिए मिली हुई है। अलबत्ता अब अमेरिकी प्रशासन ने इन्हें अपने देश लौट जाने का निर्देश भी दे दिया है। यदि इस प्रावधान में सरकार संशोधन नहीं करती है तो इसी माह 30 जून को इन्हें नौकरियों से बेदखल कर दिया जाएगा। हालांकि अमेरिकी कंपनियां ट्रंप की इन एकतरफा नीतियों से प्रसन्न नहीं हैं। उन्होंने अमेरिकी संसद (सीनेट) के जरिए विरोध भी जताया है। यहां के पेशेवर ट्रंप की इस पहल को आत्मघाती बता रहे हैं। जल्दबाजी में अमल में लाई जा रही इन नीतियों में अनेक कमियां हैं, जिनका स्थानीय स्तर पर विरोध भी हो रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी आईटी रोजगारधारकों ने पिछले दिनों न्यूजर्सी और पेंसिल्वेनिया में प्रदर्शन कर ग्रीन कार्ड बैकलॉग खत्म करने की मांग की है। इससे ऐसे लाखों लोग प्रभावित होने जा रहे हैं, जो कई वर्षों से वहां हैं और जल्दी ही समय-सीमा के दायरे में आकर उनका एच-4 वीजा समाप्त होने वाला है।

यदि वाकई ऐसा होता है तो आज अमेरिका में जो विदेशी प्रवासियों के बच्चे हैं, उनकी उम्र 21 साल पूरी होते ही, उनकी रहने की वैधता खत्म हो जाएगी। दरअसल एच-1 बी वीजा वाले नौकरीपेशा के पत्नी और बच्चों के लिए एच-4 वीजा जारी किया जाता है, लेकिन बच्चों की 21 साल उम्र पूरी होने के साथ ही इसकी वैधता खत्म हो जाती है। ट्रंप चिंतित हैं कि आईटी टेक्नोक्रेट के बहाने जो आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिकी संस्थाओं व कंपनियों पर प्रभावी होते जा रहे हैं, वे मूल अमेरिकियों के लिए बेरोजगारी का कारण भी बन रहे हैं। 2008 में अमेरिका में हुई जनगणना के आधार पर यहां की कुल आबादी 30.50 करोड़ है। इसमें से नवाजो और चरूकी जनजातीय लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन नस्लीय भेदभाव के चलते अमेरिकी समाज इन्हें दोयम दृष्टि से देखता है। इस कारण ये आधुनिक सुविधाओं से उसी तरह से लगभग वंचित हैं, जिस तरह से भारत में आदिवासी समाज है। अभावग्रस्त यही लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।

अमेरिका में कुल आबादी में से 13.66 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने को विवश हैं। ट्रंप शायद ऐसे ही लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए वीजा नियमों को कठोर बना रहे हैं लेकिन अमेरिका की समृद्धि की पृष्ठभूमि में दुनिया के प्रवासियों का ही प्रमुख योगदान रहा है।

धारा 498ए

तार्किक कसौटी पर परखना जरूरी

गीता यादव

महिलाओं के अधिकारों के लिए भारतीय संविधान और संसद उदार रही है। संविधान ने लिंग के आधार पर किसी भी किस्म के भेदभाव का निषेध किया है। 1980 के दशक में और उसके बाद महिलाओं के संरक्षण के लिए कई कानून बने और अदालती फैसले भी आए। दहेज हत्या के दोषियों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 304बी है। वर्क प्लेस पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षित करने के लिए विशाखा गाइडलाइंस हैं।महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसे ''निर्भया एक्ट' के नाम से जाना जाता है। गर्भ में शिशु हत्या को रोकने के लिए कानून बना। इसके केंद्र में भी बच्चियां हैं, लेकिन इस बीच एक महत्त्वपूर्ण कानून ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से अब बेहद कमजोर और इस वजह से बेअसर हो गया है। 1980 के दशक में दहेज के लिए बहुओं को जलाने की एक के बाद एक हो रही घटनाओं के बाद महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता में एक विशेष धारा 498ए जोड़ी गई। धारा 498ए ने महिलाओं को एक जरूरी संरक्षण दिया। चूंकि भारतीय दंड संहिता में 498ए के अलावा और कोई धारा नहीं है, जिसके तहत परिवार के अंदर होने वाली हिंसा या अत्याचार करने वाले को सजा दिलाई जा सके, इसलिए क्रूरता के तमाम तरह के मामलों में 498ए के तहत ही मुकदमे दर्ज कराए जाने लगे। कहना न होगा कि 498ए कितना महत्त्वपूर्ण कानून है। खासकर तब जबकि अब भी हर साल लगभग साढ़े आठ हजार केस दहेज हत्या के दर्ज होते हैं। लेकिन 27 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा बनाम यूपी सरकार केस में यह माना कि 498ए का दुरुपयोग हो रहा है और निदरेष लोग इसमें फंसाए जा रहे हैं।

इस तर्क को अदालत में सही माना गया कि इस धारा में सिर्फ 15 फीसद मामलों में ही सजा होती है, जो यह साबित करता है कि कानून का दुरु पयोग हो रहा है। इसके अलावा छिटपुट ऐसे मामलों को अदालत में उठाया गया, जिसमें इस एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। एससी-एसटी अत्याचार निरोधक अधिनियम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने माना था कि इस कानून का दुरु पयोग हो रहा है। बहरहाल, यह एक दोषपूर्ण तर्क है कि किसी कानून के तहत सजाएं नहीं हो रही हैं, तो कानून ही गलत है। किसी कानून के तहत कम सजाएं होने के कई कारण हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, केस लड़ने वाले कमजोर हो सकते हैं, जांच एजेंसियों का झुकाव मजबूत पक्ष की ओर होता है, या न्याय की सुस्त रफ्तार के कारण आरोप लगाने वाला पक्ष थक सकता है और कोर्ट से बाहर समझौते कर लेता है। बाहर समझौते के बाद भी ये मामले अदालतों में पड़े रहते हैं क्योंकि केस वापस लेने की व्यवस्था इस कानून में नहीं है। पेंडिंग केसेस की वजह से यह कह दिया जाता है कि आरोप फर्जी थे। दोषसिद्ध न होना, जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था की खामियों के कारण भी हो सकता है। इसके लिए कानून जिम्मेदार नहीं है; फिर यह जिम्मेदारी तो कानून लागू करने वाली संस्थाओं की है कि किसी कानून के तहत निदरेष को परेशानी न हो। गौर करने की बात है, कि आपराधिक मामलों में अदालत का काम सजा दिलवाना है, न कि समझौते की संभावना को जिंदा रखना। यह काम परिवार, समाज और पंचायतों का है। इन संस्थाओं के असफल होने पर ही कोई मामला न्याय की उम्मीद में कोर्ट तक पहुंचता है। यह भी देखना चाहिए कि दुरु पयोग के चंद मामलों के मुकाबले, इस कानून से महिलाओं को कितनी बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 498ए के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर शिकायत पहले जिला स्तरीय फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जाएगी। इन कमेटियों का गठन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करेगी। इनकी सहमति के बिना पुलिस 498ए में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। यह फैसला मूल कानून के खिलाफ है, जिसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। कमेटी को गिरफ्तारी के बारे में फैसला लेने का अधिकार देना एक तरह से आपराधिक मामलों की जांच में सिविल सोसायटी को शामिल करना है। इस फैसले की सीमाओं और खामियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बैच इस फैसले पर फिर से विचार कर रही है। इसकी आखिरी सुनवाई 23 अप्रैल, 2018 को हुई है। फैसला अभी आना है। इस मामले में कानून के मूल स्वरूप को बचाने के लिए सरकार को सख्त रु ख अपनाना चाहिए। धारा 498ए में कोर्ट आगे भी कोई बदलाव न करे, इसलिए आवश्यक है कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए।

योगी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम, राज्यपाल खुद संभालें बागडोर : अखिलेश

लखनऊ । समाजवादी पार्टी (सपा) के एक प्रतिनिधिमण्डल ने यहां राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नीत भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में यही अच्छा होगा कि राज्यपाल सूबे की प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में ले लें. सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि पार्टी प्रतिनिधिमण्डल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और राज्य की भाजपा सरकार की निष्क्रियता और उसके राग द्वेषपूर्ण आचरण के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने की मांग की। ज्ञापन में पार्टी ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो गई है. अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ नहीं है।

जनता मंहगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है। समाजवादी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के हित की जो योजनाएं लागू की थीं, वे सब या तो बंद हो गई है या उनके लिए बजट नहीं दिया जा रहा है. कानून व्यवस्था चौपट है. दिनदहाड़े हत्या, लूट अपहरण हो रहे हैं. महिलाओं, बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं. पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास के मामले में दशकों पीछे कर दिया है. ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता एवं विकास के लिए यही अच्छा होगा कि राज्यपाल प्रशासनिक व्यवस्था खुद अपने हाथ में ले लें. ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल है. कर्ज, फसल की बर्बादी, समय से गन्ना किसानों के भुगतान ना होने और भाजपा के वादे के अनुसार कृषि उत्पाद का लागत का डेढ़ गुना अतिरिक्त मूल्य ना मिलने से निराश-परेशान किसान आत्महत्या को मजबूर है।

बुंदेलखण्ड के महोबा जिले में 27, बांदा में 12 तथा हमीरपुर में 11 किसानों की जान जा चुकी है. प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने राज्यपाल से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल ने सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बदनाम करने की नीयत से अभियान छेड़ रखा है, ताकि जनता का ध्यान सरकार की असफलताओं की ओर नहीं जा सके. प्रतिनिधिमण्डल में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल तथा विधान परिषद सदस्य एस.आर.एस. यादव सदस्य शामिल थे।

यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने राजभर की पार्टी के विधायक को बताया चोर

वाराणसी । उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच दूरी बढ़ती ही जा रही है। एसबीएसपी अध्यतक्ष ओमप्रकाश राजभर के सरकार पर लगातार हमले के बीच बीजे पीप्रदेश अध्यतक्ष डा. महेंद्र नाथ पांडेय ने एसबीएसपी विधायक को चोर बता दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यजक्ष मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। डेप्युटी सीएम दिनेश शर्मा के साथ वह अजगरा विधानसभा क्षेत्र के चोलापुर में पं. दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और नए ओपन संकायों का लोकार्पण किया। समारोह में स्थायनीय विधायक एसबीएसपी के कैलाश सोनकर के मौजूद न होने को लेकर चर्चाएं होती रहीं। डेप्युटी सीएम दिनेश शर्मा के सामने विधायक को कहा चोर कार्यक्रम के दौरान रही सही कसर डॉ. पांडेय ने पूरी कर दी। शिलापट्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, 'यहां का विधायक चोर निकल गया इसलिए उसका नाम इसमें नहीं लिखा गया है। यह बात डेप्युतटी सीएम को भी बता दी है। इस पर खूब तालियां बजीं, कुछ ही देर में इसका विडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यहक्ष ने कहा कि विधायक पर लगे भ्रष्टोचार के आरोपों की जांच कराई जाएगी। उधर, विधायक कैलाश सोनकर के खिलाफ लोगों ने एक बार फिर जिला मुख्योलय पर सिर मुंडवा कर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि सरकारी योजनओं का लाभ दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये हड़प लिया गया है। विधायक कैलाश सोनकर ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए किसी तरह के घोटाले से इनकार किया है।

संक्षिप्त खबर

प्रतापगढ़ : घर में घुसकर महिला की चाकू से हत्या

प्रतापगढ़। (वार्ता) उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की चाकू से हत्या कर दी और 2800 रुपया लूटकर ले गये । पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि कोतवाली इलाके में मंगलवार रात करीब नौ बजे भगवा निवासी राजकुमार पाण्डे अपने घर से करीब 200 मीटर दूर अपने निर्माणाधीन मकान पर गये थे । कुछ देर बाद जब वे घर पहुंचे तो उनकी 60 वर्षीय पत्नी प्रेमादेवी का रक्तरंजित शव पड़ा मिला। उसका पर्स खुला था जिसमें करीब 2800 रुपये थे जो गायब मिले । घटना के समय महिला खाना बनाने की तैयारी कर रही थी । उन्होंने बताया कि श्री पाण्डे का घर रेल लाइन के किनारे है और महिला को अकेला देख लूटपाट के इरादे से नशे के आदी बदमाश घर में घुसे और प्रेमादेवी की सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या कर दी । उन्होंने बताया घटना के समय महिला घर में अकेली थी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है । प्रथम दृष्टया रेल लाइन के किनारे रहने वाले नशे के आदी बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है । पुलिस अन्य बिन्दुओं पर भी जांच कर रही है ।

बुलंदशहर में सोते समय एक वृद्ध की हत्या

बुलंदशहर । (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में अज्ञात हमावरों ने सोते समय एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी । पुलिस सूत्रों ने यहां बताया किर अरनिया निवासी 62 वर्षीय कृपाल चौहान पंचायतघर के पास अपने घेर में सो रहा था । बुधवार सुबह अज्ञात हमलावरों ने सिर पर चोट पहुंचाकर श्री चौहान की हत्या कर दी । प्रथम दृष्टया हत्या का कारण रंजिश है । मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन शुरु कर दी । उन्होंने बताया इस संबंध परिजनों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है । शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ।

गोंडा में तस्कर गिरफ्तार

गोंडा ।(वार्ता)उत्तर प्रदेश में गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र की पुलिस ने बुद्धवार को एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से चार लाख रूपये मूल्य का गांजा बरामद किया। पुलिस के अनुसार तस्कर पिंटू चोरी छिपे गांजा लाकर बिफी करने की फिराक में था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सुबह उसे मलारी गांव के पास 15 किलो गांजा के साथ दबोच लिया। बरामद गांजा की कीमत चार लाख बतायी जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर बस्ती जिले के हरैया क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी निशानदेही पर तस्करी में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

बस्ती में ट्रक से कुचलकर 3 व्यक्तियों की मौत

बस्ती।(वार्ता) उत्तर प्रदेश में बस्ती के वाल्टर गंज क्षेत्र में को एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों को कुचल दिया जिससे तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मोटरसाइकिल सवार चंद्रपति (25) निवासी पिपरा बस्ती, दुर्गेश(23) निवासी गोरे आभार संतकबीर नगर एवं सर्वजीत (24) निवासी आगई बस्ती को मंगलवार रात में एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वाणिज्य कर विभाग ने छापा मारकर दुकान एवं गोदाम किए सीज

बहराइच।(वार्ता) उत्तर प्रदेश में बहराइच के गायघाट बाजार में मेंथा के दो कंपनियों पर विशेष अनुसंधान शाखा सचल दल गोंडा एवं वाणिज्य कर की टीम ने छापा मारकर दो दुकान व तीन गोदाम को सीज कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विशेष अनुसंधान शाखा सचल दल गोंडा के संयुक्त आयुक्त के पी साहू एवं वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त राहुल कुमार द्विवेदी की अगुवाई में मंगलवार को गायघाट बाजार में फैजान ट्रेडिंग कंपनी व जिलानी ट्रेडिंग कंपनी के दो दुकान व तीन गोदामों पर छापेमारी की। व्यवसायी मौके से खिसक गए। इस मामले में दुकान और गोदामों पर नोटिस भी चस्पा की गई है। संयुक्त आयुक्त साहू ने बताया कि दोनों कंपनियों की ओर से मेंथा आदि का व्यवसाय बिना टैक्स अदा किए हुए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि दुकान व गोदामों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। समय से अभिलेख उपस्थित न करने और टैक्स अदा न करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बब्बू यादव, अभिषेक शुक्ला, संतोष कुमार सिंह, दुर्गेश कुमार, मनीष कुमार, रिजवान अहमद, अभय सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी सुनील जैन, केदारनाथ वर्मा व मोतीपुर थाने की पुलिस भी मौजूद रही।

हापुड़ में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 6 लोगों की मौत, 4 घायल

हापुड़ । (वार्ता) उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार छह लोगों की मृत्यु हो गई जबकि चार गंभीर रुप से घायल हो गये । पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने यहां बताया कि बुधवार तड़के करीब चार बजे गढ़मुक्तेश्वर इलाके में स्याना फलइओवर के पास बिजली घर के समाने मेरठ की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े दूध के ट्रक के पीछे जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि पांच लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि एक व्यक्ति ने बाद में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि गंभीर रुप से घायल चार लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है । मृतकों की शिनाख्त कराई जा रही है ।

इविवि के पूर्व कुलपति और कार्यपरिषद के वर्तमान सदस्य ने दिया इस्तीफा

इलाहाबाद। (वार्ता) इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि)के कुलपति रतन लाल हंगलू के रजिस्ट्रार हितेश लव को पद से सेवा समाप्त करने के विरोध में पूर्व कुलपति और इविवि कार्यपरिषद के वर्तमान सदस्य प्रो सी एल क्षेत्रपाल ने राष्टपति को अपना इस्तीफा पत्र द्वारा भेज दिया। प्रो क्षेत्रपाल ने मंगलवार को भेजे अपने इस्तीफा पत्र में कुलपति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विश्वविद्यालय को एक अखाड़ा बना कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यपरिषद की बैठक को भी मजाक बनाकर रख दिया है। कार्यपरिषद के सदस्यों को न/न एजेंडा दिया जाता है और न ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोई चर्चा की जाती है। उन्होंने राष्टपति को इस्तीफा पत्र भेजने के साथ ही सूचना मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर, यूजीसी के चेयरमैन प्रो डी पी सिंह को भी इसकी एक प्रति भेज दी है।

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया गया जबकि कुलपति के ऊपर भी एमएचआरडी की दो जांच कमेटियों ने कई गंभीर आरोप लगाये हैं। प्रो क्षेत्रपाल ने अपने इस्तीफे में यह आरोप भी लगाया है कि कार्यपरिषद की बैठक में अधिकतर सदस्य कुलपति की हां में हां मिलाते हैं। कर्नल हितेश लव के मामले पर उन्होंने अपनी बात रखनी चाही लेकिन उनकी बात को कोई तवज्जों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं लेकिन इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार कर्नल लव को अपना पक्ष रखने के लिए एक मौका तक नहीं दिया गया। देश की 35 साल तक सेवा करने वाले अधिकारी कर्नल हितेश लव, जिसके दामन पर भ्रष्टाचार के एक दाग तक नहीं है, उन्हें बिना एक मौका दिये हटाना न्यायोचित नहीं है।

योग दिवस पर राजनाथ राजभवन में होंगे शामिल

लखनऊ। (वार्ता) केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह राजभवन में होने वाले चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसमें 1,000 से अधिक लोग योगाभ्यास करेंगे।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण लखनऊ में सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ योग करेंगी। यह कार्यक्रम लखनऊ के केन्द्रीय कमाल मुख्यालय हो होगा। यद्यपि योग दिवस समारोह पूरे राज्य में मनाया जाएगा। 21 जून को योगा दिवस पर प्रदेश के मंत्री लखनऊ समेत सभी 75 जिलों में योगाभ्यास करेंगे। लखनऊ में इसके लिये दस पार्कों का चयन किया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक राजभवन में मंगलवार को योगाभ्यास में शामिल हुये। उन्होने योगा में अपनी विशेष रूचि दिखायी है। राज भवन में योगा दिवस के अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और राज्य आयुष मत्री धरम सिंह सैनी शामिल होंगे। योग समारोह राजभवन लॉन में सुबह 0600 बजे से 0800 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागी कुंभ-2019 के प्रतीक वाली सफेद टी-शर्ट पहनेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अंतर्राष्टीय योग दिवस समारोह में शामिल होगें ।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांण्डेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शामिल होंगे। योग समारोह में शामिल होने के लिये प्रदेश सभी सांसदो, मंत्रियों और विधायको को जिले आवंटित किये गये है।

लखनऊ के दो होटलों में आग लगने पर मालिकों के खिलाफ मुकदमा

लखनऊ। (वार्ता) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को दो होटलों में आग लगने से हुई छह लोगों की मृत्यु को लेकर नाका पुलिस ने होटल मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि घटना के संबंध में थाना नाका पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337, 338, 285, 304 के तहत एसएसजे इन्टरनेशनल होटल के मालिक सुरेन्द्र जायसवाल तथा विराट होटल के मालिक अर्पित जायसवाल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार इस मामले की जांच कराने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किये है। सूत्रों ने बताया कि आग लगने का कारण शार्ट सर्किट को माना जा रहा है।

घटना में सभी मृतकों को शिनाख्त हो गई है तथा मृतकों में पटना से यहां सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए अभिनाश(24) एवं उसका पिता गणेश प्रसाद (45) भी शामिल है। गौरतलब है कि राजधानी लखनऊ के नाका क्षेत्र स्थित दो होटलों में आग लगने से छह लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा कई लोग घायल हो गए थे।

पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास पर निगाहें

स्वास्थ मंत्री ने मांगा अखिलेश या मुलायम का बंगला

लखनऊ । पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास खाली करने का बवाल अभी थम नहीं पाया था कि उनको आवंटित कराने का घमासान तेज हो गया है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को लिखी चिट्ठी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव द्वारा खाली किए बंगलों में से किसी एक को उन्हें आवंटित करने का आग्रह किया है।सिद्धार्थनाथ का कहना है कि इस समय वह जिस सरकारी बंगले 19 गौतमपल्ली में रहते हैं, वह काफी छोटा है और वहां कैंप कार्यालय में स्टाफ व आगंतुकों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इससे आम जनता को असुविधा भी होती है। सिद्धार्थनाथ ने पत्र में बंगला संख्या-4 या 5, विक्रमादित्य मार्ग का उल्लेख करते हुए दोनों में से किसी एक को आवंटित करने की मांग की है। 4, विक्रमादित्य मार्ग अखिलेश यादव व बंगला संख्या 5, मुलायम सिंह यादव को आवंटित था। स्वास्थ्य मंत्री अपने बंगले 19, गौतमपल्ली में वर्षा में छत से पानी टपकने की शिकायतें करते रहे हैं। यह बंगला सपा सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्र को आवंटित था। आलीशान महल जैसे अखिलेश के बंगले को सजाने में सरकारी खजाने से 42 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हुई थी। बंगले को खाली करते समय उसमें हुई तोडफ़ोड़ की जांच लोक निर्माण विभाग की एक कमेटी कर रही है। राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला ने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह द्वारा लिखे गए पत्र से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से खाली हुए बंगलों के आवंटन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकारी बंगले को खाली करने के बाद उसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आवंटित करने की सलाह दी थी। उन्होंने चुटकी भी ली थी कि बंगले पर कई मंत्रियों की निगाह है। अखिलेश व मुलायम सिंह के बंगलों के अलावा राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह का आवास पाने के अरमान भी कई वरिष्ठ मंत्री व अधिकारी लगाए हैं। गौतमपल्ली में रह रहे एक अन्य कैबिनेट मंत्री का मन भी अपने आवास में नहीं लग रहा है।

सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पावर को बढ़ावा देने का लिया निर्णय

लखनऊ, 20 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक 4300 मेगावाट क्षमता का ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप स्थापना का लक्ष्य रखते हुए राज्य के सार्वजनिक, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पावर को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी शासनादेश में यह जानकारी दी गई है। शासनादेश के अनुसार इन भवनों पर रेस्को (रिन्यूवल इनर्जी सप्लाई कम्पनी) द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जायेगी। आदेशानुसार रेस्को मोड के तहत कार्यालयों के भवन पर रिन्यूवल इनर्जी सप्लाई कम्पनी (रेस्को) द्वारा अपने वित्तीय निवेश से सोलर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप संयत्रों की स्थापना की जायेगी। संयत्र का रखरखाव व संचालन पूर्णरूप से रेस्को द्वारा होगा। रेस्को द्वारा स्थापित किये जा रहे ग्रिड संयोजित रूफटॉप संयत्र से उत्पादित ऊर्जा का 25 वर्ष अथवा उससे कम अवधि के लिए एक नियत टैरिफ पर फय संबंधित कार्यालय द्वारा रेस्को के साथ पावर की खरीद का अनुबन्ध होगा।

शासनादेश में कहा कि रेस्को द्वारा स्थापित संयत्र से उत्पादित ऊर्जा की आपूर्ति संबंधित विभाग कार्यालय को पारम्परिक ग्रिड पावर की आपूर्ति टैरिफ से कम नियत टैरिफ पर उपलब्ध करायी जायेगी। रूफटाप संयत्र की स्थापना नेटमीटरिंग प्रणाली पर होगी, जिससे कि कार्यालय भवन द्वारा रेस्को द्वारा स्थापित रूफटाप संयत्र से प्राप्त की जा रही सौर पावर खपत से अधिक होने पर सरप्लस पावर ग्रिड में फीड की जा सकेगी, जिसका लाभ संबंधित कार्यालय भवन को माह में प्राप्त हो रहे विद्युत बिल में प्राप्त होगा। सरकारी कार्यालयों एवं भवनों पर रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट संयत्रों की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरआई) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापित होगी। सरकारी उपफम सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा प्रदेश में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों पर रेस्को द्वारा रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट संयत्रों की स्थापना के लिए सितम्बर, 2017 में आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के द्वारा रेस्को का चिन्हीकरण किया गया है, जिसके द्वारा 3.91 रुपये प्रति यूनिट की विद्युत आपूर्ति दर निश्चित की गई है। यदि भविष्य में इन दरों में कमी होती है तो नई परियोजनाओं पर संशोधित दरें प्रभावी मानी जायेगी। आदेश के अनुसार सौर ऊर्जा नीति 2017 के फियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों एवं कार्यालयों पर सोलर रूफटाप संयत्रों की स्थापना के लिए यूपीनेडा अथवा भारत सरकार की अन्य नोडल एजेन्सी द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जायेगी। आदेश में बताया कि निविदा में प्राप्त टैरिफ 3.91 रुपये प्रति यूनिट अथवा जैसा समय-समय पर सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित होगी, से अनधिक रहे और चयनित रेस्को तकनीकी रूप से कार्य के लिए सक्षम हो।

बहराइच : कुत्तों ने हमला कर 3 दिन में 22 लोगों को किया घायल

बहराइच। (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सीतापुर के बाद अब बहराइच जिले के फखरपुर क्षेत्र में कुत्तों ने पिछले तीन दिनों में ग्रामीणों पर हमला कर 22 लोगों को घायल कर दिया है।सूत्रों ने बताया कि कोठवल कला गांव में छह-सात के झुंड में कुत्तों ने ग्रामीणों पर हमलाकर लोगों को घायल कर दिया। इस मामले में कोठवल कला के ग्राम प्रधान राम खिलावन ने इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से भी की, लेकिन अभी तक गांव में कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को यहां निजी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया है। इनमें 18 लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। जबकि चार लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर शाम कुत्तों ने गांव के रावेंद्र कुमार, बीरबल, हरपाल, शर्मावती, प्रेमनाथ, सूरज, लकी नोंच कर घायल कर दिया तथा इनके सहित पिछले तीन दिनों में कुत्तों के हमले से गांव के 22 लोग घायल हुए है। पिछले तीन दिनों में कुत्तों के हमले बढ गए है और इससे पूर्व मिहींपुरवा के उर्रा में कुत्तों ने एक मासूम समेत तीन लोगों को नोंचकर लहूलुहान कर दिया था। ग्राम प्रधान के अनुसार गांव में कुत्तों का आतंक व्याप्त है। क्षेत्र में कुत्तों की संख्या अधिक हो गयी है, लेकिन पांच से छह की संख्या में कुत्ते तीन दिन से राहगीरों पर हमलावर हो रहे हैं। इस मामले में वन विभाग के साथ तहसील को सूचना दी गई है, लेकिन अब तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है।

सरकारी स्कूल का मुख्य गेट गिरा, दो बच्चे घायल

सूरत (ईएमएस)। शहर के वेड रोड स्थित एक सरकारी स्कूल का मुख्य गेट गिरने से उसके नीचे दो बच्चे दबकर घायल हो गए। एम्ब्युलैंस 108 से दोनों घायल बच्चों को सूरत के स्मीमेर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सूरत के वेड रोड स्थित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित स्कूल का मुख्य दरवाजा अचानक ढह गया। यह घटना उस समय हुई जब दो बच्चे उसे खोलने का प्रयास कर रहे थे। दरवाजा ढहते ही दोनों बच्चे उसके नीचे दब गए। आसपास मौजूद लोगों ने फौरन दरवाजा हटाकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला। हांलाकि इस घटना में दोनों बच्चे घायल हो गए, जिन्हें एम्ब्युलैंस 108 की मदद से सूरत के स्मीमेर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद अभिभावकों की स्कूल में भीड़ जमा हो गई। गौरतलब है पिछले साल सूरत के लिंबायत क्षेत्र की स्कूल में ऐसी ही घटना में एक बच्चे की मौत हो गई थी।

कांग्रेस के हाथ से निकली अहमदाबाद जिला पंचायत, भाजपा का कमल खिला

अहमदाबाद (ईएमएस)। अहमदाबाद जिला पंचायत में सत्ता बरकरार रखने के कांग्रेस के हरसंभव प्रयास निष्फल रहे। कांग्रेस के बागी सदस्यों की मदद से भाजपा ने अहमदाबाद जिला पंचायत पर कब्जा कर लिया। अहमदाबाद जिला पंचायत में कांग्रेस के 18 और भाजपा के 13 सदस्य थे। कांग्रेस बहुमत में थी, परंतु बागियों ने भाजपा का कमल खिला दिया। जिला पंचायत में ढाई साल की अवधि पूर्ण होने पर प्रमुख और उप प्रमुख का आज चुनाव हुआ। कांग्रेस की ओर से अमरसिंह ठाकोर और भाजपा के जितेन्द्रसिंह चौहाण ने प्रमुख की दावेदारी की थी। जबकि उप प्रमुख के लिए कांग्रेस से अमरसिंह सोलंकी और भाजपा से भावीबेन पटेल के बीच मुकाबला था। कांग्रेस को अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी, परंतु ऐन वक्त में उसके ही सदस्यों ने धोखा दे दिया। कांग्रेस के मनुजी ठाकोर, जगदीश मेणिया, देवकुंवरबा दाइमा, इच्छाबेन पटेल, ठाकरशी राठौड़ और कालूजी ठाकोर ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर अहमदाबाद जिला पंचायत उसकी झोली में डाल दी। हांलाकि कांग्रेस को पहले ही आशंका थी कि जिला पंचायत हासिल करने के लिए भाजपा सभी राजनीतिक हथकंडे अपनाएगी और इसी कारण उसने अपने सदस्यों को पिछले दस दिनों से शहर के बाहर भेज दिया था। बीती रात कांग्रेस के सदस्यों को अहमदाबाद लाया गया था और एक होटल में ठहराया गया था। परंतु कांग्रेस की पूरी कवायद धरी की धरी रह गई और उसके हाथ से अहमदाबाद जिला पंचायत निकल गई। कांग्रेस के बागी सदस्यों की मदद से भाजपा के जितेन्द्रसिंह चौहाण प्रमुख और भावीबेन पटेल उप प्रमुख चुन ली गईं। इस बीच कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने एक एक सदस्य को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। गौरतलब है अहमदाबाद जिला पंचायत की प्रमुख पुष्पाबेन डाभी की अवधि पूर्ण होने पर कांग्रेस पंचायत सदस्य अमरसिंह को नया प्रमुख बनाना चाहती थी। परंतु कारोबारी सदस्य मनुजी ठाकोर प्रमुख पद हासिल करना चाहते थे। मनुजी ठाकोर और कांग्रेस के जिला प्रमुख खोडाजी ठाकोर के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से मनुजी ठाकोर को लगता था कि खोडाजी ठाकोर की वजह से उनका पत्ता कट गया। अब अहमदाबाद जिला पंचायत के प्रमुख के लिए उनका कटने से मनुजी ठाकोर नाराज थे।

स्वर्ण जयंती राजधानी एवं गुजरात मेल में कैप्टन ऑफ दे ट्रेन की सेवा उपलब्ध

अहमदाद (ईएमएस)। पश्चिम रेलवे पर पहली बार अहमदाबाद मंडल पर अहमदाबाद से चलनेवाली स्वर्ण जयंती राजधानी और गुजरात मेल में कैप्टन ऑफ द ट्रेन की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय प्रकाश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 19 जून से अहमदाबाद की गुजरात मेल और स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में यह सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इन ट्रेनों में कैप्टन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन में ओवरऑल लीडर और सभी ऑन बोर्ड रेलवे स्टाफ तथा आउटसोर्स स्टाफ का इंचार्ज होगा, जो यात्रियों को ऑन बोर्ड दी जानेवाली सभी सुविधाओं की सुचारू व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन कैप्टन को अपनी यूनिफार्म के साथ बांह पर एक बैज पहनना होगा जिस पर कैप्टन ऑफ द ट्रेन अंकित होगा। जिससे यात्री उसे आसानी से पहचान सकें। ट्रेन में कार्यरत सभी कर्मचारी चाहे वे रेलवे से या आउटसोर्स से सभी को ट्रेन कैप्टन को रिपोर्ट करना होगा और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। ट्रेन कैप्टन के निर्देशों के यात्री हित में पालन नहीं करने पर रेल प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

कांग्रेस शासित 5 जिला पंचायतों में भाजपा का कमल खिला : जीतु वाघाणी

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतु वाघाणी ने आज कहा कि कांग्रेस शासित 5 जिला पंचायतों समेत 21 तहसील पंचायतों में कमल खिला है। इसी के साथ राज्य की 13 जिला पंचायत और 114 तहसील पंचायतों में भाजपा ने सत्ता हासिल कर ली है। अहमदाबाद, पाटण, महीसागर, दाहोद और भावनगर जिला पंचायतों में भाजपा का कमल खिला है। किसान, आदिवासी, ओबीसी बहुल क्षेत्र में भाजपा की जीत दिशासूचक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है और राज्य की जनता को उस पर भरोसा नहीं है। राज्य की जनता ही नहीं बल्कि कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के लिए सत्ता सर्वोपरी है और इसी वजह से उसके निर्वाचित सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्ववाली केन्द्र सरकार और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अगुवाई वाली गुजरात सरकार पर भरोसा करते हुए जनहित कार्यों से जुड़ने का फैसला किया है। जनता के आक्रोश को देख भाजपा की विकासलक्षी राजनीति को समर्थन करनेवाले कांग्रेस के सभी सदस्यों का जीतु वाघाणी ने स्वागत किया। वाघाणी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सदस्यों को संभाल नहीं पाई, जिसकी वजह से आज जिला व तहसील पंचायतें गंवा दीं। कांग्रेस की सत्ता में कहीं सेवा भाव नहीं है। भाजपा ने कभी जोड़तोड़ या लोकतंत्र के खिलाफ राजनीति नहीं की। कांग्रेस हमेशा सत्ता की राजनीति करती है। कांग्रेस ने मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखनेके बजाए अपने सदस्यों को पत्र लिखा होता आज उसे जिला व तहसील पंचायतें गंवानी नहीं पड़ती। हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के बजाए कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है।

ढाई साल के बजाए सवा साल में प्रमुख और उप प्रमुख बदलने का सौदा करने वाली कांग्रेस किस मुंह से लोकतंत्र की बात करती है। उन्होंने इससे पहले भी सभी नगर पालिका, तहसील पंचायत, जिला पंचायतों के उप चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी। सरपंचों के चुनाव में भी 80 प्रतिशत से ज्यादा भाजपा समर्थित सरपंच विजयी हुए थे।

दोस्ती के नाम पर कलंक:दोस्त ने ही दोस्त का रेत दिया गला

इकलौते बेटे के जाने से घर में छाया मातम

सूरत। दोस्ती के नाम पर कलंक लगाने का एक किस्सा सामने आया है, जिसमें एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का चाकू से गला काट दिया। मृतक अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। उसके जाने से पूरे घर में मातम छा गया। लोग बिलख-बिलखकर रो रहे थे। लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया।

ऊन भिंडी बाजार स्थित फैयाज फईम मंसूरी (22) अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने पिता के साथ सोने-चांदी में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी के धंधे से जुड़ा था।

मंगलवार को फैयाज एक दोस्त के साथ घर के करीब खड़ा था। इस दौरान एक और दोस्त मोहम्मद अशरफ शेख भी वहां पहुंचा। अशरफ ने फैयाज से समय पूछा। न जाने इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि अशरफ ने चाकू निकालकर फैयाज का गला रेत दिया। इससे फैयाज जमीन पर गिर पड़ा। वह अपने पिता के साथ सोने-चांदी में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी के धंधे से जुड़ा था।

मंगलवार को फैयाज एक दोस्त के साथ घर के करीब खड़ा था। इस दौरान एक और दोस्त मोहम्मद अशरफ शेख भी वहां पहुंचा। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उधर घटना के बाद अशरफ फरार हो गया। फैयाज अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। उसके चले जाने से पूरे परिवार में मातम छा गया।

४ जुलाई से बैठक एलोटमेन्ट होगा

नीट के मेरिटलिस्ट की २६ जून को घोषणा की जायेगी

अहमदाबाद। अहमदाबाद सहित की राज्यभर की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रक्रिया १५ जून से शुरू हो चुकी है। आगामी २५ जून तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद स्टेट लेवल का नीट यूजी २०१८ का काउन्सेलिंग का शिडयूल जारी किया गया है। रजिस्टर्ड विद्यार्थियों का स्टेट मेरिटलिस्ट २६ जून को घोषणा की जायेगी और २७ जून से चोइस फीलिंग, चोइस लोकिंग शुरू होगी, जो ३० ज ून तक चलेगी। पहले राउन्ड की सीट एलोटमेन्ट की प्रक्रिया ४ जुलाई से शुरू की जायेगी। अब ५ से १२ जुलाई तक डॉक्युमेन्ट्स वेरिफिकेशन के साथ एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जायेगी और ५ से २१ जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉलेज लेवल से होगा। अहमदाबाद के वीएस अस्पताल की एनएचएल म्युनिसिपल कॉलेज की २५० बैठक, मणिनगर की एलजी कॉलेज की १५० सीट सहित राजकोट, भावनगर, जामनगर, बडौदा, सूरत यह कुल १२५० बैठक पर एडमिशन दिए जायेंगे, जबकि सरकारी-कॉर्पोरेशन हस्तक की, पीपीपी और सेल्फ फाईनान्स की २५ से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की ३००० से ज्यादा बैठक पर एडमिशन दिए जायेंगे। इस वर्ष में नीट २०१८ में गत वर्ष की तुलना में कट ऑफ में कटौती हुई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ ११९, दिव्यांगों के लिए १०७ और आरक्षण के लिए ९६ रहा है। दो राउन्ड के बाद मोक अप राउन्ड ५ अगस्त से शुरू होगी, जिसमें रिक्त बैठकों की जानकारी दी जायेगी। ५ और ६ अगस्त को चोइस फीलिंग और लोकिंग बाद ९ अगस्त को मेरिटलिस्ट की घोषणा की जायेगी। कॉलेज लेवल एडमिशन अगस्त में स्टेट वेकन्सी राउन्ड द्वारा होगा, जो १३ से १८ अगस्त रहेगा। जबकि ३० जुलाई को दूसरे राउन्ड की बैठकें एलोट होगी, जिसके लिए ३ अगस्त तक विद्यार्थियों को मेडिकल और डेन्टल में रिपोर्ट करना पड़ेगा।

वडोदरा में देर रात दो गुटों में संघर्ष, पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले छोड़े

वडोदरा। शहर के वाडी ताईवाडा के पास मंगलवार की रात 11 बजे दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसके दो घंटे बाद याकूतपुरा इलाके में भी दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के तीन गोले छोड़े। घटना इस प्रकार है कि वाड़ी में एक युवक की पिटाई की गई थी। इससे दो गुट के लोग आमने-सामने आ गए। फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इससे माहौल तंग बन गया। उसके बाद याकूतपुरा में भी दो गुटों में तीखी झड़पें हुई।

गुजरात के वन मंत्री गनपत वसावा की प्रतिक्रिया

शेरों को परेशान किया, तो हो सकती हैं ७ साल की सजा

गांधीनगर। अब एशियाई शेरों का उत्पीडन करने पर वन्यजीव सुरक्षान अधिनियम १९७२ के तहत ७ साल की जेल की सजा भी काटनी पड सकती हैं। गुजरात सरकार ने एशियाई शेरों के बढते गैरकानूनी लायन शो पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह फैसला किया है। इस अधिनियम के तहत शेरों के उत्पीडन में गैरकानूनी लायन शो, गाडी से शेरों का पीछा करना और अवैध विडियो बनाना भी शामिल हैं। इसी के साथ सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए शेरों को परेशान करते पाए जाएंगे उन पर कडी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्हें ७ साल की सजा भी सुनवाई जा सकती हैं। सरकार ने शेरों के आवास क्षेत्र के २२००० वर्ग किमी के फैलाव प्रबंधित करने ते लिए एकल प्राधिकिरण के गठन की भी घोषणा की, जो वर्तमान में चार अलग-अलग अथोरिटी के नियंत्रण में हैं। गुजरात के वन मंत्री गनपत वसावा ने कहा, हमने वन अधिकारियों को जानवरों को परेशान करने वाले के खिलाफ शिकार का मामला दर्ज करने को कहा हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐक्ट के अनुसार शिकार का मतलब सिर्फ जानवर को मारना नहीं हैं। यह शेर या बाघ जैसे जानवरों पर किसी तरह के उत्पीडन की दशा में भी लागू होता हैं। बता दें कि ऐक्ट की अनुसूची १ के तहत आने वाले जानवरों को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत उच्च स्तर की सुरक्षा दी जाती हैं। बता दें कि पिछले महीने गैरकानूनी रुप से गुजरात के गिरगढडा में लायन शो करने के आरोप में ७ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनके पास से एशियाई शेरों को लालच देकर परेशान करने वाले कई विडियो पुलिस को प्राप्त हुए हैं। इन विडियो के जरिए कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां लायन शो के नाम पर शेरों का उत्पीडन किया जा रहा था। इन विडियो में शेर प्रलोभन देने वालों पर हमला न करके परेशान होते हैं। शेरों का यह व्यवहार वन अधिकारियों के लिए चिंता का सबब बन गया हैं।

गुरूवार को विश्व योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद नवरंगपुरा सरदार पटेल स्टेडियम में योग के लिए तैयारियां शुरू की गई थी।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

सचिन में दो ने अलग-अलग जगहों पर लगाई फांसी

सूरत। प्रथम घटना में एक व्यक्ति दारू की लत होने के कारण बेरोजगारी से तंग आकर घर में रोज झगड़े करने के कारण दारु पीने के लिए पैसे ना मिलने से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी घटना में एक 11 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सचिन विस्तार रहने वाले कृष्णचंद्र जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 साल की है कृष्ण कुंज अपार्टमेंट 1986 से रहते थे और दारु पीने की लत होने के कारण घर में हमेशा झगडा रहता था और बेरोजगार होते हुए भी रोज शाम को दारु पीने के लिए घर से पैसे मांगने के कारण तंग आकर घर के बाहर कपड़े सुखाने की डोरी से फांसी लगाकर अपने जीवन का अंत कर लिया।

उपसभापति के चुनाव से साफ होगा, कितना एकजुट है विपक्ष

भारतीय जनता पार्टी के पास १०६ सांसदों का समर्थन है, जिसमें एआईएडीएमके के १४ एमपी शामिल हैं

गांधीनगर। राज्य सभा के उपसभापति पी.जे. कुरियन १ जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को नए डेप्युटी चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना है। एक तरफ बीजेपी आम सहमति बनाकर इस पोस्ट को अपने उम्मीदवार के लिए सुरक्षित करना चाहती है तो वहीं विपक्षी पार्टियां एक संयुक्त उम्मीदवार की संभावनाएं तलाश रही हैं। ऐसे में २०१९ के लोकसभा चुनाव से पहले यह विपक्षी एकता का असली टेस्ट भी साबित होगा। बेजेपी के पास १०६ सांसदों का समर्थन है, जिसमें एआईएडीएमके के १४ एमपी शामिल हैं। उधर, विपक्षी पार्टियों का सम्मिलित आंकड़ा ११७ तक पहुंच रहा हैं, जिसमें टीडीपी भी शामिल है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com